



जागत



चौपाल से
भोपाल तक

भोपाल, सोमवार, 04-10 सितंबर 2023 वर्ष-9, अंक-21

भोपाल, इंदौर, उज्जैन, सागर, मुँरैना, रीवा, शिवपुरी से एक साथ प्रकाशित

पृष्ठ :-8, मूल्य :- 2 रुपए

महुआ चाय, महुआ पावडर, महुआ स्नेक्स का स्वाद भा गया

यूरोप में महका मप्र का महुआ

» उमरिया, अलीराजपुर, सीधी, सिंगरौली, डिंडोरी, मंडला, शहडोल और बैतूल में ज्यादा उत्पादन

» महुआ बीनने वाले परिवारों की आमदनी बढ़ रही और वे महुआ पेड़ों को सहेजने के लिए प्रेरित हो रहे

भोपाल। जागत गांव हमार

मध्यप्रदेश का महुआ अब यूरोप के नागरिकों में एथनिक फूड के रूप में पहचान बना रहा है। यूरोप के फूड मार्केट में महुआ से बने खाद्य पदार्थ दिखने लगे हैं और पसंद किए जा रहे हैं। यूके की लंदन स्थित कंपनी ओ-फारेस्ट ने महुआ के कई प्रोडक्ट बाजार में उतारे हैं। इनमें मुख्य रूप से महुआ चाय, महुआ पावडर, महुआ निब-भुना महुआ मुख्य रूप से पसंद किये जा रहे हैं। ओ-फारेस्ट ने मध्यप्रदेश से 200 टन महुआ खरीदने का समझौता किया है। इससे महुआ बीनने वाले जनजातीय परिवारों को सीधा लाभ मिलेगा। महुआ जनजातीय समाज के लिए अमृत फल है। महुआ लड्डू और महुआ से बनी देशी हेरिटेज मंदिरा उनके पारम्परिक व्यंजन हैं।

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने देश में सबसे पहले महुआ और अन्य वनोपजों का समर्थन मूल्य घोषित किया था। इससे महुआ बीनने वाले जनजातीय परिवारों को विचौलियों से मुक्ति मिल गई है। उन्हें बाजार में भी अच्छे दाम मिलने लगे हैं। महुआ अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जाने से महुआ बीनने वाले जनजातीय परिवारों को अच्छी कीमत मिलेगी। महुआ का समर्थन मूल्य 35 रुपए किलो है। यूरोप में महुआ की खपत होने से उन्हें 100 से 110 रुपए प्रति किलो का मूल्य मिलेगा।



महुआ-समृद्ध प्रदेश

प्रदेश में महुआ बहुतायत में होता है। एक मौसम में करीब 7 लाख 55 हजार क्विंटल तक मिल जाता है। पूरी तरह महुआ फूल से लदा एक पेड़ 100 किलो तक महुआ देता है। करीब 3 लाख 77 हजार परिवार महुआ बीनकर अपना घर-परिवार चलाते हैं। एक परिवार कम से कम तीन पेड़ों से महुआ बीनता है। साल में औसतन दो क्विंटल तक महुआ बीन लेता है। कुल महुआ संग्रहण का 50 प्रतिशत उमरिया, अलीराजपुर, सीधी, सिंगरौली, डिंडोरी, मंडला, शहडोल और बैतूल जिलों से होता है।

खान-पान संस्कृति

यूरोप के बाजार में महुआ से बने खाद्य पदार्थों की बढ़ती पसंद के बारे में पूछने पर मीरा शाह बताती हैं कि लाखों लोग एक देश से दूसरे देश आते-जाते हैं। वे अन्य देशों की खान-पान संस्कृति से भी परिचित होना चाहते हैं। इस प्रकार मध्यप्रदेश के महुआ से बने खाद्य पदार्थों के प्रति रुचि बढ़ रही है। यूके में जनसंख्या की विविधता है इसलिए दुनिया के हर देश का व्यंजन और खाद्य पदार्थ यहां मिल जाता है।

हेरिटेज वाइन

महुआ फूल से बनी मंदिरा को हेरिटेज वाइन के रूप में प्रस्तुत करने के लिए राज्य सरकार ने नीति बनाई है। जनजातीय क्षेत्र के स्व-सहायता समूहों को ही इसे बनाने का लाइसेंस दिया जाएगा। हर स्व-सहायता समूह अपने उत्पाद का अलग नाम रख सकता है। जिलों में एक से अधिक स्व-सहायता समूहों को भी लाइसेंस मिल सकता है। स्व-सहायता समूहों के सदस्यों में कम से कम 50 प्रतिशत महिला सदस्य होना चाहिए।

किसान मित्रों की 12 सितंबर को होने जा रही महापंचायत

नाथ सरकार में बर्खास्त किसान मित्रों को बहाल करेंगे शिवराज

भोपाल। जागत गांव हमार

मध्यप्रदेश में 15 महीने की कमलनाथ सरकार का दंश झेल रहे राज्य के कृषक मित्र और दीदी के शिवराज में आच्छे दिन आने वाले हैं। लंबे इंतजार के बाद बर्खास्त कृषक मित्र और दीदी को पुनः कृषि विभाग में काम करने का अवसर मिलने जा रहा है। गौरतलब है कि चार साल पूर्व मध्य प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने प्रदेश के 28 हजार किसान मित्र और दीदी को पद से बर्खास्त कर बेरोजगार कर दिया था। लेकिन मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार बर्खास्त किए गए सभी किसान मित्र, दीदी को बहाल करने जा रही है। मध्य प्रदेश के किसान मित्र और दीदी की महापंचायत 12 सितंबर-2023 को भोपाल में होने जा रही है। वहीं सूत्रों का कहना है कि मुख्यमंत्री किसान मित्रों और दीदी को नियमित कर्मचारियों की तर्ज पर तमाम सुविधाओं की सौगात देंगे। यहाँ नहीं, सातवें वेतनमान का भी लाभ मिलेगा और किसी किसान मित्र को अब नौकरी से नहीं निकाला जाएगा।



दिला चुके कृषि कर्मण अवॉर्ड

केंद्र और राज्य सरकारों की खेती की योजनाओं का किसानों के बीच प्रचार-प्रसार करने वाले किसान मित्र और किसान दीदी प्रदेश में 16.44 रुपए प्रतिदिन के मान से काम कर रहे थे। यानी राज्य सरकार इन्हें साल में 6000 रुपए का भुगतान करती थी। जबकि ये गांव-गांव जाकर किसानों को नई योजनाएं एवं तकनीक के बारे में समझाते थे। अप्रैल 2014 से प्रदेश के 54 हजार गांवों में तैनात किए गए थे। इस बीच सरकार ने खेती के क्षेत्र में तरकीबें करके कई कृषि कर्मण अवॉर्ड जीते हैं।

केंद्र को लिखा था पत्र

मध्यप्रदेश तत्कालीन कृषि विभाग के प्रमुख सचिव डॉ. राजेश राजीरा ने 4 जुन 2017 को भारत सरकार को पत्र भेजा था, जिसमें उन्होंने बताया कि कृषक मित्र खेती से जुड़ी योजनाओं में सक्रिय भागीदारी कर रहे हैं। आवागमन एवं अन्य सुविधाएं महंगी हो गई हैं। ऐसे में उनके भत्ता और वेतन बढ़ाने पर विचार किया जाए। लेकिन कुछ नहीं हुआ। इसके बाद भी सभी काम करते रहे।



मध्यप्रदेश के कृषक मित्र-दीदी हमारे परिवार के सदस्य हैं। अगले महीने से हम इनको काम पर लगाने जा रहे हैं। बजट बढ़ाने के संदर्भ में भी हमारी बात हो गई है। जब हमारे कृषक मित्र दुखी रहेंगे तो हम सुखी कैसे रह सकते हैं। मैंने मंत्री बनते ही इनसे वादा किया था कि सब को दोबारा नौकरी में वापस लिया जाएगा। मुख्यमंत्री बहुत अच्छे हैं। वो किसी को निराश नहीं करेंगे।

-कमल पटेल, कृषि मंत्री, मप्र

महुआ फल प्रकृति का उपहार

मध्यप्रदेश में सीएम शिवराज के निर्देश पर महुआ संग्रहकों को कई सुविधाएं दी गई हैं। वही ओ-फारेस्ट कंपनी की सह-संस्थापक मीरा शाह बताती हैं कि महुआ फल प्रकृति का उपहार है। मध्यप्रदेश सरकार के साथ काम करते हुए हमें बेहद खुशी है कि हमें महुआ फल की उपज को उत्सव की तरह मनाने और जनजातीय संस्कृति में इसका संरक्षण करने का अवसर मिला। समर्थन मूल्य पर महुआ फूल की खरीदी सरकार का एक बड़ा कदम है। इससे खाद्य पदार्थ के रूप में महुआ का महत्व बढ़ेगा और इसकी पहुंच बड़े बाजारों तक होगी।

अगले माह मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान योजना की करेंगे घोषणा

चुनावी सौगात! सिंचाई पंप के लिए 50 प्रतिशत सब्सिडी देगी सरकार

भोपाल। जागत गांव हमार

मध्य प्रदेश के किसानों को सिंचाई पंप खरीदने के लिए शिवराज सरकार चुनावी सौगात के रूप में अब सब्सिडी देने जा रही है। इसके लिए ऊर्जा विभाग ने प्रस्ताव तैयार किया है। पंप खरीदने की राशि तीन लाख रुपए निर्धारित की गई है। इसमें डेढ़ लाख रुपए राज्य सरकार सब्सिडी देगी। खास बात यह है कि पंप खरीदने के लिए दी जाने वाली सब्सिडी में एपीएल या बीपीएल को बाध्यता नहीं रखी गई है। संपन्न किसान भी इसका लाभ ले सकेंगे। अगले माह मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इस योजना की घोषणा कर सकते हैं। इधर भारत सरकार द्वारा 2019 में शुरू कुसुम योजना भी देशभर में संचालित है। इस योजना में किसानों को सोलर पंप खरीदने के लिए सब्सिडी दी जाती है।

वित्त विभाग असहमत

किसानों को पंप खरीदने के लिए दी जाने वाली सब्सिडी के प्रस्ताव पर वित्त विभाग ने असहमति जताई है। वित्त विभाग का तर्क है कि इससे ढाई हजार करोड़ रुपए का वित्तीय भार आएगा। फिलहाल इस प्रस्ताव पर ऊर्जा विभाग और वित्त विभाग के बीच पत्राचार किया जा रहा है। हालांकि मुख्यमंत्री सचिवालय से इस प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी गई है।



» केंद्र सरकार द्वारा 2019 में शुरू कुसुम योजना भी देश में संचालित

» अब पंप की सब्सिडी में एपीएल या बीपीएल की बाध्यता नहीं रहेगी

एक करोड़ किसान

मध्य प्रदेश में एक करोड़ से अधिक किसान हैं। यह संख्या कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा संचारित किसानों के बैंक खातों के आधार पर है। इनमें 67 प्रतिशत किसान ऐसे हैं जिनके पास दो हेक्टेयर कृषि भूमि है। इसमें प्रथम चरण में 50 हजार किसानों को पंप खरीदने के लिए 50 प्रतिशत सब्सिडी देने की तैयारी है। बाद में इस संख्या को बढ़ाया जाना प्रस्तावित है।

1.20 लाख देगा ऊर्जा विभाग

किसानों को कृषि पंप खरीदने के लिए एक लाख 20 हजार रुपए ऊर्जा विभाग देगा और 30 हजार रुपए संबंधित क्षेत्र की विद्युत वितरण कंपनी द्वारा दिए जाएंगे। इस तरह एक लाख 50 हजार रुपए की राशि शासन द्वारा सब्सिडी के रूप में दी जाएगी।

-जनसंपर्क मंत्री ने किया बटरफ्लाई पार्क का लोकार्पण व रेप्टाईल पार्क का शिलान्यास

» फलीभूत होते ही सफारी को विश्व में अनूठा स्थान प्राप्त हो जाएगा
» व्हाइट टाइगर सफारी की स्थापना से लेकर लगातार कर रहे विकास

मुकुंदपुर व्हाइट टाइगर सफारी को बनाएं सफेद बाघों का ब्रीडिंग सेंटर

भोपाल।

जनसंपर्क मंत्री राजेन्द्र शुक्ल ने महाराजा मारतण्ड सिंह व्हाइट टाइगर सफारी मुकुंदपुर में बटरफ्लाई पार्क का लोकार्पण किया। मंत्री शुक्ल ने 3 करोड़ रुपए की लागत से बनाए जा रहे रेप्टाईल पार्क का भूमि-पूजन भी किया। पार्क में 12 किस्मों के सांप रखे जाएंगे। मंत्री शुक्ल ने दिल्ली से प्राप्त सफेद बाघ को व्हाइट टाइगर सफारी स्थित बाड़े में छोड़ा। मंत्री ने कहा कि सफारी में आज सफेद बाघ के रूप में नया मेहमान आया है। ग्वालियर से शीघ्र ही सफेद बाघों का नया जोड़ा मिलने की उम्मीद है। व्हाइट टाइगर सफारी को सफेद बाघों का ब्रीडिंग सेंटर बनाने की दिशा में वन विभाग के विशेषज्ञ लगातार प्रयास कर रहे हैं। इन प्रयासों के फलीभूत होते ही सफारी को विश्व में अनूठा स्थान प्राप्त हो जाएगा।



250 वन्य-प्राणी

मंत्री ने कहा कि व्हाइट टाइगर सफारी की स्थापना वर्ष 2016 में की गयी थी तब से लगातार इसका विकास और विस्तार किया जा रहा है। आज इसमें लगभग 250 वन्य-प्राणी हैं। आज विश्व स्तरीय बटरफ्लाई पार्क का शुभारंभ किया गया है। साथ ही रेप्टाईल पार्क निर्माण के लिए भूमि-पूजन भी किया गया है। सफारी के निर्माण के बाद विन्ध्य में 46 सालों के बाद सफेद बाघों की वापसी हुई। इसके विकास के लिए लगातार प्रयास किए जाते रहेंगे।

बढ़ गए सैलानी

समारोह में ग्रामीण विकास राज्य मंत्री रामखेलावन पटेल ने कहा कि व्हाइट टाइगर सफारी विन्ध्य क्षेत्र के प्रमुख पर्यटन स्थल के रूप में अपना स्थान बना चुका है। सफारी में पर्यटकों की संख्या तथा आय में दिनों-दिन वृद्धि हो रही है। आज बटरफ्लाई पार्क तथा नये सफेद बाघ की प्राप्ति से दो उपलब्धियां हासिल हुई हैं।

34 बाड़ों का निर्माण पूरा

सफारी के संचालक सूरज सिंह सैयाम ने बताया कि प्रस्तावित 40 में से 34 बाड़ों का निर्माण पूरा हो गया है। शेष का तेजी से निर्माण कार्य किया जा रहा है। यह सफारी प्राकृतिक वातावरण में निर्मित विश्व का सबसे सुन्दर प्राणी उद्यान है। कार्यक्रम में नगर निगम के अध्यक्ष व्यंकटेश पांडेय, विवेक दुबे, मुख्य वन संरक्षक राजेश राय, जिला रेडक्रास समिति के अध्यक्ष डॉ. प्रभाकर चतुर्वेदी, डीएफओ रीवा अनुपम शर्मा, डीएफओ सतना विपिन पटेल तथा बड़ी संख्या में आमजन उपस्थित रहे।



-सीएम ने अधिकारियों से किया विचार-विमर्श अल्पवर्षा से उत्पन्न चुनौतियों से निपटने ताकत से काम करेंगे



भोपाल। जगन्त गांव हमार

-सीएम शिवराज बोले-नुकसान से बचने किसानों को फसल उत्पादन के पैटर्न को बदलें -1500 करोड़ रुपए की लागत के आईटीसी की खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों का शिलान्यास

किसान चिंता न करें, हर संकट से निपट लेगी राज्य सरकार

18 प्रतिशत की कृषि विकास दर

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सीहोर के औद्योगिक क्षेत्र बड़ियाखेड़ी में आईटीसी कंपनी की कुल 1500 करोड़ रुपए के निवेश से स्थापित होने वाली दो इकाइयों-इंटीग्रेटेड फूड मैनुफैक्चरिंग एंड लॉजिस्टिक्स फॅसिलिटी और सस्टेनेबल पैकेजिंग प्रोडक्ट्स मैनुफैक्चरिंग फॅसिलिटी का शिलान्यास किया। ये दोनों इकाइयां 57 एकड़ में लगेंगी। इससे 5000 लोगों को रोजगार मिलेगा। इस फूड प्लांट में आईटीसी के विश्वस्तरीय भारतीय ब्रांड जैसे देश का नंबर-1 आटा ब्रांड आशीर्वाद, सनफीस्ट बिस्कुट और यिप्पी नूटल्स का उत्पादन होगा, जबकि मोल्डेड फाइबर प्रोडक्ट्स प्लांट सस्टेनेबल पैकेजिंग के क्षेत्र में नए मानक बनाएगा। इससे इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं, एफएमसीजी और फूड एवं बेवरेज सेक्टर में पैकेजिंग के लिए प्लास्टिक का विकल्प मिलेगा। सीहोर में फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में आईटीसी का यह निवेश राज्य के मैनुफैक्चरिंग सेक्टर में मूल्य सृजित करेगा और एग्री-वैल्यू चेन में सहयोग देगा।

शिलान्यास कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि खेती में मध्यप्रदेश ने देश के सभी राज्यों को पीछे छोड़ दिया है। मध्यप्रदेश ने डेढ़ दशकों तक 18 प्रतिशत की कृषि विकास दर प्राप्त कर चमत्कार किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कृषि फसल नुकसान से बचने और खेती को लाभ का धंधा बनाने के लिए फसल उत्पादन के पैटर्न को बदलना होगा। परंपरागत फसलों के साथ-साथ व्यावसायिक फसलों जैसे औषधीय फसलों का भी उत्पादन भी आवश्यक है।

खेती आधारित उद्योग लगाने के प्रयास

सीएम ने कहा कि खरीफ की फसल में अधिकतर सोयाबीन और धान ही लगाते हैं और कई बार एक फसल पर संकट आने से किसान को नुकसान होता है। अलग-अलग फसलों की किस्मों से किसानों को अधिक से अधिक लाभ हो सके। इसके लिए आईटीसी ने 7000 एकड़ में तुलसी, अश्वधा, कलौजी की खेती की है। खेती पर आधारित उद्योग धंधे लगाने का निरंतर प्रयास किया जा रहा है, ताकि किसानों को अपनी फसलों का अच्छा दाम और स्थानीय नागरिकों को रोजगार मिले।

15 लाख 42,750 करोड़ के निवेश प्रस्ताव

मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में 15 लाख 42 हजार 750 करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव आए हैं। आईटीसी कंपनी ने भी प्रस्ताव दिया था जिसके तहत बड़ियाखेड़ी में 1500 करोड़ रुपए का निवेश हो रहा है। आईटीसी किसानों के साथ मिलकर उद्योग और खेती के विकास दोनों के लिए काम कर रही है। इस पहल से सीहोर और आसपास के 5000 लोगों को रोजगार मिलेगा।

बिजली की मांग बढ़ेगी सीएम ने कहा कि बारिश कम होने के कारण बिजली की मांग बढ़ गई है। पहले 7 हजार मेगावाट की आवश्यकता थी जो बढ़कर 15000 मेगावाट की मांग बढ़ गई है। आईटीसी लिमिटेड के चेयरमैन सजीव पुरी ने सीहोर में आईटीसी की नई निवेश परियोजनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी। कार्यक्रम में इलावर विधायक कृष्ण सिंह वर्मा, सीहोर विधायक सुरेश राय, आधा विधायक रघुनाथ मालवीय, जिला पंचायत अध्यक्ष गोपाल सिंह इजीनियर, सीहोर जनपद अध्यक्ष नावडी बाई बारना, नगर पालिका अध्यक्ष प्रियंसा राठौर उपस्थित थे।

रहे थे। बैठक में मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैस तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि अगस्त माह में वर्षा बहुत कम हुई है। अल्पवर्षा के कारण फसलें प्रभावित हो रही हैं। खरीफ की फसलों संकट में हैं। इस संकट की स्थिति से निपटने के लिए पूरी ताकत से काम करेंगे। बिजली की डिमांड भी बढ़ गई है। इसके लिए बेहतर व्यवस्था भी करेंगे। डेम से पानी छोड़कर फसलों को बचाया जाएगा। ग्रामीण युवाओं को रोजगार देने की व्यवस्था पर भी ध्यान दिया जाता रहेगा। पेयजल और निस्तार के पानी की व्यवस्था करेंगे।

डेमों का परीक्षण कर लें

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि जल उपयोगिता समिति की बैठक जल्द कर लें। जहां पानी उपलब्ध है वहां डेम से पानी छोड़ने की व्यवस्था करें। डेमों का परीक्षण कर लें। डेमों में अभी कितना पानी उपलब्ध है, इसकी जानकारी भी लें। जिला प्रशासन को आवश्यक निर्देश दिए जाएं। किसानों को सिंचाई के संबंध में एडवाइजरी जारी करें। कि बिजली की बेहतर व्यवस्था करें।



-रामचरित मानस में लिखा है-फूले कांस सकल महि छाई, जिमि वर्षा रितु प्रगत बुढ़ाई। इसका मतलब ही यही है-कांस में फूल आ गए तो बरसात खत्म हो गई।

50 साल बाद ऐसा सूखा

भोपाल। जागत गांव द्वाारा

मध्यप्रदेश में अगस्त लगभग सूखा बीत गया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को बारिश के लिए प्रार्थना करने के लिए कहना पड़ा। भोपाल में उन्होंने कहा कि मैं रात भर परेशान रहा, क्योंकि पूरा अगस्त सूखा गया। इस कारण बांध पूरे नहीं भरे। बिजली की डिमांड भी एकदम बढ़ गई है, क्योंकि फसलें अगर बचना हैं तो पानी देना है। ऐसी डिमांड आज तक कभी नहीं आई। सीएम ने हाथ जोड़ते हुए कहा कि हम भरसक कोशिश कर रहे हैं अपनी तरफ से कि चीजें ठीक रहें, लेकिन यह स्थिति संकट की है। 50 साल में ऐसा संकट सूखे का नहीं आया। अभी भादों चल रहा है। मैं भी भगवान से प्रार्थना करूंगा, आप भी प्रार्थना करें कि बारिश एक बार जरूर हो जाए, ताकि हम फसलें बचा सकें और बाकी व्यवस्थाएं भी ठीक चलती रहें।

तीन साल से सितंबर में अच्छी बारिश

मध्यप्रदेश में मानसून के लिहाज से सितंबर का महीना भी खास रहता है। जुलाई-अगस्त के बाद बचा कोटा सितंबर की बारिश पूरा कर देती है। पिछले 10 में से 5 साल बारिश ने सितंबर का कोटा पूरा किया है, लेकिन इस बार ऐसी उम्मीद नहीं है। मौसम वैज्ञानिकों की मानें तो अबकी बार सामान्य की 50 फीसदी बारिश होने का ही अनुमान है। इसकी वजह स्ट्रॉंग सिस्टम का एक्टिव नहीं होना है। मौसम वैज्ञानिक डॉ. वेदप्रकाश सिंह के अनुसार 4 से 5 सितंबर के आसपास बंगाल की खाड़ी में सिस्टम एक्टिव हो रहा है। 6 से 7 सितंबर तक लो प्रेशर एरिया एक्टिव हो सकता है। इससे पूर्वी हिस्से में मध्यम से भारी बारिश हो सकती है। यह सिस्टम 18 से 19 सितंबर तक एक्टिव रह सकता है।

» सबसे ज्यादा बारिश नरसिंहपुर में हुई है। यहां अब तक हुई बारिश का आंकड़ा 41 इंच से अधिक है।

» सिवनी में 37.53 इंच, मंडला-जबलपुर में 35, डिंडोरी में 34 से ज्यादा बारिश हो चुकी है।

मग्न में 16 फीसदी बारिश कम

मध्यप्रदेश में 1 जून से 31 अगस्त तक औसत 26.06 इंच बारिश हो चुकी है, जबकि अब तक 31.16 इंच बारिश होनी चाहिए थी। इस हिसाब से 16 फीसदी कम बारिश हुई है। पूर्वी हिस्से में औसत से 13 फीसदी और पश्चिमी हिस्से में 20 फीसदी बारिश कम हुई है। प्रदेश में 24 जून को मानसून एंटर हुआ था। इसके बाद कुछ दिन अच्छे बरसा, लेकिन जुलाई और अगस्त में सामान्य से कम बारिश हुई। यदि सितंबर में 158 मिमी यानी 6 इंच बारिश होने का कोटा पूरा भी हो जाता है तो भी कई जिलों में सामान्य से कम बारिश होगी।

10 साल में सितंबर में कितना गिरा पानी

भोपाल: साल 2013 से 2022 के बीच 10 साल के आंकड़ों पर नजर डालते तो वर्ष 2019 में सबसे ज्यादा बारिश हुई थी। इस साल सितंबर में 22 इंच से ज्यादा बारिश हो गई थी। पिछले साल भी 8 इंच से ज्यादा बारिश हुई थी। भोपाल में सितंबर की सामान्य बारिश करीब 7 इंच

इंदौर: 10 साल में वर्ष 2019 में 19 इंच से ज्यादा बारिश हुई थी। इसके बाद से ही लगातार कोटे से ज्यादा बारिश हो रही है। इंदौर की सामान्य बारिश करीब 7 इंच है।

जबलपुर: पिछले साल 10 इंच से ज्यादा पानी गिरा था। इससे पहले 2019 में 16 इंच से अधिक बारिश दर्ज की गई थी। बाकी सालों में कोटे से कम बारिश हुई है। इस बार कोटा पूरा होने की उम्मीद है। जबलपुर में सामान्य बारिश का आंकड़ा 10.5 इंच है।

ग्वालियर: पिछले 10 साल में साल 2016 में सबसे कम बारिश हुई थी। इस साल सितंबर महीने में एक इंच पानी भी नहीं गिरा था। पिछले दो साल से बारिश का आंकड़ा 5 इंच से ज्यादा है। हालांकि, सामान्य बारिश का कोटा (5.8 इंच) पूरा नहीं हो पाया है।

-ऊर्जा विभाग ने बनाया कटौती का प्लान

किसानों को सिंचाई के लिए सात घंटे ही मिलेगी बिजली

कम बारिश की वजह से मंडराया संकट, कम बारिश से नदी, तालाब-डैम खाली

इधर, मध्यप्रदेश में मानसून की बेरुखी ने सरकार की टेंशन बढ़ा दी है। अगस्त में हुई कम बारिश से नदी, तालाब और डैम खाली हैं। जिसके चलते हाइड्रो पावर जेनरेशन यानी पानी से बिजली बनाने में कमी आई है। सितंबर के पहले दिन बिजली की डिमांड 14.5 हजार मेगावाट को पार कर गई है। ऐसे में ग्रामीण क्षेत्रों में ऊर्जा विभाग ने बिजली सप्लाई में कटौती का प्लान जारी किया है। इसके लिए जिलों को तीन कैटेगरी में बांटा गया है। जिलों में ग्रामीण क्षेत्र में होने वाली बिजली सप्लाई 7 घंटे तक ही रहेगी। 24 घंटे के अंतराल में 17 घंटे तक कटौती की जाएगी। बिजली कंपनियों अभी तक ग्रामीण क्षेत्रों में सिंचाई के लिए 10 घंटे बिजली दे रही थी। अब बारिश के संकट के चलते बने हालातों को देखते हुए कटौती करने का निर्णय लिया गया है। यह प्लान 2 सितंबर से दो-तीन दिन के लिए लागू करने के नाम पर जारी किए गए हैं।

तीन कैटेगरी में बांटे जिले-

प्लान के अनुसार प्रदेश के सभी जिलों को तीन कैटेगरी में बांटा गया है। ए, बी और सी कैटेगरी बनाकर जिले तय किए गए हैं। विभाग के अनुसार बिजली संकट की स्थिति को देखते हुए इन जिलों में ग्रामीण क्षेत्रों में सिंचाई के लिए दी जाने वाली बिजली में कटौती की जाएगी।

जिलेवार कैटेगरी

ए कैटेगरी: मंडला, पन्ना, रीवा, अनूपपुर, दमोह, भिंड, गुना, ग्वालियर, अशोक नगर, दतिया और मुरैना जिले शामिल हैं।

बी कैटेगरी: सिवनी, शहडोल, भोपाल सिटी, शाजापुर, मंदसौर, बुरहानपुर, जबलपुर सिटी, विदिशा, बालाघाट, सीधी, रायसेन, झाबुआ, रतलाम, छतरपुर, डिंडोरी, कटनी, राजगढ़, सीहोर, टीकमगढ़, नरसिंहगढ़, इंदौर सिटी, सागर, सतना, धार, बड़वानी, देवास, आगर, नीमच, उज्जैन, बैतूल, खंडवा, खरगोन, छिन्वाड़ा, श्यामपुर, शिवपुरी, होशंगाबाद, हरदा जिले और बुधनी विद्युत संधाग शामिल किए गए हैं।

सी कैटेगरी: सिंगरौली और उमरिया।

अलग-अलग समय पर रहेगी बिजली

ग्रामीण क्षेत्रों में 11 केवी फीडर से की जाने वाली सप्लाई में कटौती को लेकर जो प्लान जारी किया गया है, उसमें तीनों ही कैटेगरी के जिलों में रात 12 बजे से सुबह 4 बजे तक और इसके बाद सुबह 10 से दोपहर बाद 4 के बीच बिजली सप्लाई का टाइम अलग-अलग शेड्यूल में तय किया गया है। ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि इस दौरान बिजली की डिमांड कम होती है। इसके अलावा सुबह 5 से 10 के बीच और शाम 5 से रात 11 बजे के बीच पीक आवर्स के लोड के चलते इस अवधि में जिलों में ग्रामीण क्षेत्र की फीडर सप्लाई बंद रहेगी।

■ बारिश न होने के कारण गर्मी बढ़ी है। इसके कारण प्रदेश में बिजली की डिमांड 14500 मेगावाट को पार कर गई है। सप्लाई बनाए रखने के लिए बाजार से भी बिजली खरीदी कर रहे हैं। संजय दुबे, प्रमुख सचिव, ऊर्जा विभाग

सावधान! भारत में सूखे की दीर्घकालिक भविष्यवाणी

इस साल फरवरी में, एसआरएम इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, भारत और स्कॉलकोवो इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, रूस के वैज्ञानिकों ने भारत में सूखे की दीर्घकालिक भविष्यवाणी का प्रयास किया। उन्होंने डीप लर्निंग मशीन मॉडल को तैनात किया जिसे दीर्घकालिक अल्पकालिक स्मृति कहा जाता है, जिसका काम है 117 वर्षों की वर्षा और सूखे की स्थिति का विश्लेषण करना। यह मॉडल पिछले डेटा रूझानों को उठाता है जिनका

उपयोग 2018-2027 के भविष्य के रूझानों का पूर्वानुमान लगाने के लिए किया गया है। इसके निष्कर्षों से पता चलता है कि जुलाई 2022 से अप्रैल 2023 तक हल्की बारिश की अवधि थी और अगले अप्रैल 2027 से अक्टूबर 2027 भी ऐसी ही होगी। इसका मतलब है कि इस पूर्वानुमान सीमा में अन्य सभी अवधियां हल्के सूखे की होंगी। इस अध्ययन में कहा गया है कि 2027 तक कर्नाटक, गुजरात और उत्तराखंड राज्य गंभीर सूखे से प्रभावित

होंगे, जबकि अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, केरल, महाराष्ट्र, पंजाब, तमिलनाडु और तेलंगाना मध्यम सूखे से प्रभावित होंगे। बिहार, छत्तीसगढ़, जम्मू-कश्मीर, झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना और सिक्किम में अच्छी बारिश होगी, लेकिन हर दूसरे साल सूखा पड़ेगा। सूखे को उस आपदा के रूप में जाना जाता है जिसे व्यक्ति दूर से देख सकता है और इस प्रकार उसे कम करने का अवसर दे सकता है।

बदलते मौसम में पर्यावरण अनुकूल कृषि की जरूरत



डॉ. सत्येंद्र पाल सिंह
प्रधान वैज्ञानिक एवं प्रमुख, कृषि विज्ञान केंद्र, लहार (भिंड)

साल दर साल मौसम का बदलता स्वरूप खेती-किसानी के लिए चुनौती बन रहा है। जलवायु में हो रहे यह परिवर्तन कृषि के लिए शुभ संकेत नहीं हैं। एक तरफ जहां विश्व की बढ़ती हुई आबादी के लिए खाद्य पदार्थों की मांग बढ़ रही है। पूरे विश्व में जलवायु परिवर्तन के कारण मौसमी घटनाएं खेती-किसानी के सामने रोज नई चुनौती पैदा कर रही हैं।

निरंतर देखने में आ रहा है कि वर्षा के दिन घट रहे हैं। दूसरी तरफ वर्षा की चरमता के चलते 2 से 3 दिन के भीतर ही अत्यधिक वर्षा हो जाती है। इसके बाद जरूरत होने पर भी कई-कई दिनों तक बरसात के दिनों में भी पानी नहीं बरसता है। इस कारण लंबे इंटरसपेस के चलते वर्षा पर आधारित खरीफ मौसम की फसलें सूख जाती हैं। इस वर्ष भी कुछ ऐसा ही दिखाई पड़ रहा है। जहां जुलाई की शुरुआत में अच्छी और ज्यादा बारिश हुई। वहीं अब मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान आदि मैदानी राज्यों के कई क्षेत्रों में खेतों में खड़ी खरीफ फसलें सूख रही हैं।

किसानों के खेतों में खड़ी खरीफ फसलें इस समय पुष्पावस्था एवं दुग्धावस्था में हैं। फसलों की इन क्रान्तिक अवस्थाओं पर खेत में पर्याप्त नमी की बहुत आवश्यकता होती है। लेकिन पिछले कई दिनों से वर्षा न होने के कारण फसलें सूख रही हैं। धान जैसी अधिक पानी चाहने वाली फसल वर्षा न होने के कारण अत्यधिक संकट में है। सोयाबीन की फसल पर भी बुरा असर देखा जा सकता है।

वर्तमान हालातों को देखते हुये खरीफ फसलों का उत्पादन प्रभावित होना तय है। इस सबको देखते हुये बदलते दौर में खेतों में बदलाव की जरूरत महसूस की जा रही है।

बढ़ता तापमान और वर्षा का बदलता स्वरूप पारिस्थितिकी तंत्र को और जैव विविधता को प्रभावित कर रहा है। चरम मौसमी घटनाओं की आवृत्ति और तीव्रता से आवास, प्रजातियों के वितरण और पारिस्थितिकी संतुलन पर प्रतिकूल असर पड़ा है। हिम ग्लेशियरों की चोटियों के पिघलने से समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र पर भी प्रभाव पड़ रहा है जिससे समुद्र के जलस्तर में वृद्धि हो रही है। आने वाले समय में जलवायु परिवर्तन से कृषि के प्रभावित होने एवं फसल की पैदावार कम होने के साथ खाद्य असुरक्षा की स्थिति भी पैदा हो सकती है। जिससे किसानों की आजीविका पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। मौसम के प्रतिरूप में तेजी से आ रहे बदलाव से जल की उपलब्धता प्रभावित होगी जिससे जल की कमी होने के साथ संसाधनों को लेकर संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। बदलते हुए जलवायु परिवर्तन जैसे खतरों के कारण कृषि

उत्पादकता को प्रभावित किए बिना खाद्य सुरक्षा को सुरक्षित करने के लिए संरक्षित कृषि तकनीकों को अपनाने की आवश्यकता है। संरक्षित कृषि खेती-बाड़ी की वह पद्धति है जिसमें फसलों एवं सब्जियों को जैविक व अजैविक कारकों से बचाकर उगाया जाता है। संरक्षित कृषि पद्धति के अंतर्गत संसाधन संरक्षण तकनीकों की सहायता से टिकाऊ उत्पादन स्तर के साथ-साथ पर्यावरण को सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए फसल



का उत्पादन किया जाता है। संरक्षित कृषि मृदा की ऊपरी व निचली सतह के अंदर प्राकृतिक जैविक क्रियाओं को बढ़ाने पर आधारित है। संरक्षित कृषि में न्यूनतम जुताई, स्थाई रूप से मिट्टी को आच्छादित करके तथा फसल विविधीकरण को अपनाकर ही फसल उत्पादन के स्तर को टिकाऊ बनाया जा सकता है। संरक्षित कृषि प्रणाली में उपलब्ध संसाधनों का अधिकतम उपयोग एवं उनका संरक्षण करते हुए किसी स्थान को भौतिक, सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति के अनुसार टिकाऊ फसल उत्पादन प्राप्त करने के लिए नए-नए तरीके अपनाए जाते हैं।

बदलते जलवायु परिवर्तन में संरक्षित कृषि एक पर्याय बनकर कार्य कर सकती है। वर्तमान समय में जलवायु परिवर्तन की वजह से असमय वर्षा, अनियमित वर्षा जल का वितरण, ओलावृष्टि, अतिवृष्टि कीट व बीमारियों का प्रकोप आदि कई गंभीर समस्याएं पूरे विश्व के सामने मुंह खोलकर खड़ी हैं। हमें अपना भविष्य सुरक्षित रखने के लिए प्राकृतिक संसाधनों के उचित प्रबंधन के प्रति आज से ही सतर्क व सजग होने की आवश्यकता है। आज प्रतिस्पर्धा के दौर में किसान अधिक से

अधिक उपज प्राप्त करने के लिए अपने खेतों में अंधाधुंध रासायनिक उर्वरकों एवं कीटनाशकों का प्रयोग कर रहे हैं, जिससे मिट्टी में पौधों के लिए आवश्यक पोषक तत्वों का संतुलन दिन प्रतिदिन बिगड़ रहा है। जहां एक तरफ मृदा की घटती उत्पादन क्षमता समस्या है वहीं दूसरी तरफ जनसंख्या की वजह से खाद्यान्न सुरक्षा भी चिंता का विषय बनी हुई है। ऐसे में संरक्षित कृषि हमारे सामने एक विकल्प के रूप में उभर के सामने आती है।

संरक्षित कृषि को वजह से जमीन को उत्पादकता में काफी इजाफा होता है। साथ ही यह पानी, ऊर्जा और जमीन को उर्वरता का भी संरक्षण करती है। संरक्षित कृषि में मिट्टी की न्यूनतम जुताई की जाती है जिससे ईंधन एवं मानव श्रम दोनों की बचत होती है। क्योंकि कल्टीवेटर या रोटावेटर से मृदा को जुताई करने पर मृदा के भौतिक एवं रासायनिक गुण में परिवर्तन आता है जिससे मृदा क्षरण को बढ़ावा मिलता है।

संरक्षित कृषि प्रणाली को अपनाने से पर्यावरण एवं संसाधन दोनों का संरक्षण किया जा सकता है। न्यूनतम जुताई, फसल अवशेष का स्थाई आवरण तथा फसल विविधीकरण अपनाने से मृदा एवं जल संसाधनों की गुणवत्ता और फसल की उत्पादन क्षमता बढ़ती है। फसल अवशेष, जैव-विविधता, जैविक गतिविधियों एवं वायुवीय गुणवत्ता में बढ़ोतरी करते हैं। यह क्रिया कार्बन को संयंत्र करने एवं मृदा तापमान को नियंत्रित करने में सहायक होती है। संरक्षित खेती के अंतर्गत सिंचाई के लिए बूंद बूंद सिंचाई, सिंकलर सिंचाई तकनीकों का उपयोग किया जाता है। इसकी वजह से पानी हर पौधे तक समुचित मात्रा में पहुंचता है तथा पानी की काफी ज्यादा बचत भी होती है।

जरूरत इस बात को है कि जलवायु अनुकूल कृषि तकनीक को अपनाया जाये। कृषि वानिकी और कुशल जल प्रबंधन प्रथाओं को अधिक से अधिक बढ़ावा दिया जाए। इस दिशा में संरक्षित कृषि तकनीकों एक बेहतर और समय अनुकूल विकल्प बनकर उभरी है। आज समय की मांग है कि बदलते हुए जलवायु परिवर्तन को देखते हुए तथा विशेषकर वर्षा की असमानता एवं अनिश्चिता को देखते हुए संरक्षित कृषि को अधिक से अधिक अपनाने की आवश्यकता है। देश के किसानों, कृषि वैज्ञानिकों और सरकारों को इस दिशा में सार्थक प्रयास करना ही होगा।

सोयाबीन के प्रमुख कवक रोग एवं प्रबंध



शुभम सिंह
प्लांट पैथोलॉजी विभाग, शुएटस,
प्रयागराज (यूपी.)

सोयाबीन मेरिल एक फलीदार फसल है और भारत में मूंगफली तिलहन के बाद सोयाबीन दूसरी सबसे बड़ी फसल है। यह विविध कृषि-जलवायु परिस्थितियों में बढ़ रहा है। सोयाबीन दुनिया में तिलहन में पहले स्थान पर है, और दुनिया के कुल तेल और वसा उत्पादन में लगभग 25 प्रतिशत का योगदान देता है। सोयाबीन के क्षेत्रफल और उत्पादन के मामले में भारत क्षेत्रफल में चौथा और उत्पादन में दुनिया में पांचवें स्थान पर है।

सोयाबीन एक महत्वपूर्ण खाद्य स्रोत है। इसके मुख्य घटक प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा होते हैं। सोयाबीन में 42 प्रतिशत प्रोटीन, 22 प्रतिशत तेल, 21 प्रतिशत कार्बोहाइड्रेट, 12 प्रतिशत नमी तथा 5 प्रतिशत होती है। देश में सोयाबीन उत्पादन में मध्यप्रदेश अग्रणी है, परंतु हाल ही के कुछ वर्षों में देश में सोयाबीन उत्पादन में भारी गिरावट आई है, जिसके प्रमुख कारणों में मौसम की विपरीत परिस्थितियाँ हैं, जैसे फसल अवधि में अधिक वर्षा होना या बहुत कम वर्षा होना, ये परिस्थितियाँ रोग को बहुत हद तक बढ़ाती हैं। सोयाबीन की फसल को प्रभावित करने वाले प्रमुख कवक, रोगों के बारे में जानकारी, कारणों एवं प्रबंधन के उपाय निम्नलिखित हैं-

एनश्रेकनोज: लक्षण - सोयाबीन का एनश्रेकनोज रोग कोलेटोट्रिचम ट्रैकेटम कवक के कारण होता है। यह एक बीज एवं मृदाजनित रोग है। रोग की शुरुआती अवस्था में पत्तियों तने और फली पर गहरे भूरे रंग के अनियमित धब्बे बन जाते हैं और बाद में यह धब्बे काली संरचनाओं से भर जाते हैं। पत्तियों एवं शिराओं का पीला-भूरा होना, मुड़ना और झड़ना इस बीमारी के लक्षण हैं। संक्रमित बीज मुरझाए, फफूंदीदार और भूरे रंग के हो जाते हैं। बीजपत्रों पर लक्षण गहरे भूरे रंग के धँसा कैकर के रूप में दिखाई देते हैं।

रोग प्रबंधन: स्वस्थ या प्रमाणित बीजों का प्रयोग करें। फसल के तुरंत बाद खेत की साफ जुताई करके पौधे के अवशेषों को पूरी तरह से हटा दें। पिछले वर्षों के संक्रमित टुंड को नष्ट कर दें। अच्छी जल निकासी वाले खेत का रख-खाव करें। रोग के लक्षण दिखाई देने पर थिरम या कैप्टन या कार्बेन्डाजिम से बीज उपचार 3 ग्राम/किलोग्राम और मैनकोजेब 2.5 ग्राम/लीटर स्प्रे या कार्बेन्डाजिम 1 ग्राम/लीटर का प्रयोग करें।

अल्टरनेरिया लीफ स्पॉट: लक्षण-अल्टरनेरिया टेनुइसिमा कवक सोयाबीन के अल्टरनेरिया लीफ स्पॉट का कारक है। यह रोग पौधों की पत्तियों और फली को प्रभावित करता है। बीज छोटे होकर सिकुड़ जाते हैं।

अनियमित, फैले हुए धँसा क्षेत्र होते हैं। पर्णसमूह पर संकेंद्रित वलय के साथ भूरे, परिगलित धब्बों का दिखना, जो आसपस से जुड़कर बड़े परिगलित क्षेत्रों का निर्माण करते हैं। रोगप्रस्त पत्तियाँ सूखकर समय से पहले गिर जाती हैं।

रोग प्रबंधन: खेतों से फसल अवशेषों को नष्ट करें। थिरम+कार्बेन्डाजिम (2:1) 3 ग्राम/कि. बीज से बीज उपचार करें। मैकोजेब या कॉपर फफूंदनाशक 2.5 ग्राम/लीटर या कार्बेन्डाजिम 1 ग्राम/लीटर का प्रयोग करें।

टारगेट लीफ स्पॉट: लक्षण-कानीसोरा कैसीकोला कवक जो संक्रमित करने के लिए जाना जाता है। यह बीमारी मुख्य रूप से पत्तियों पर बाद में फलियों, तनों पर दिखाई देती है। पत्तियों पर गोल से असमान लाल-भूरे रंग के अनियमित आकार के गोल धब्बे और धावों में आमतौर पर उनके चारों ओर एक पीले-हरे रंग के धब्बे होते हैं। शब्द टारगेट स्पॉट पत्तियों पर बड़े पैच को संदर्भित करता है। गहरे भूरे रंग के धब्बे से लेकर लंबे धाव तक तनों और पंटीओल्स पर संक्रमण दिखाई देते हैं। फलियों पर छोटे गोल बैंगनी या काले धब्बे दिखाई पड़ते हैं। पत्तियाँ झड़ने लगती हैं।

रोग प्रबंधन: स्वस्थ प्रमाणित बीजों का प्रयोग करें। टारगेट लीफ स्पॉट टिएएएस को एजोक्सिस्ट्रोबिन, पाइराक्लोस्ट्रोबिन, फ्लूक्सायामरोक्सेड और प्रोथियोकोनाजोल का सावधानीपूर्वक प्रयोग करें।

देश भर में उगाई जाने वाली एक महत्वपूर्ण फसल सोयाबीन है। इनमें कई प्रकार के कवक का संक्रमण होता है, जिसके कारण उत्पादन घट रहा है। हमें यह बात हमेशा ध्यान रखनी है कि रासायनिक नियंत्रण की शुरुआत तभी करनी है जब रोग अर्थिक देहली स्तर को पार कर ले, साथ ही हमें संकेतिक रोग प्रबंधन पर ध्यान देना है। जिसकी शुरुआत बुवाई से पहले हो जाती है जैसे ग्रीष्म कालीन गहरी जुताई करना। रोग प्रतिरोधक किस्मों का चयन करना, अनुमोदित बीज दर से ज्यादा नही रखना और नत्रजन उर्वरकों का उपयोग नही करना और पोटाश पोटाश खादों का उपयोग सुनिश्चित करना।

सीमांत और छोटे किसान के लिए आजीविका निर्वाह करना एक चुनौती

भारत के लिए देश के छोटे और सीमांत किसानों की स्थिति को ध्यान में रखते हुए विकास और नीति सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है।

नवीनतम कृषि गणना सन 2010-11 के अनुसार भारत में स्वकषिप्त जोतों की संख्या 138 मिलियन थी। वहीं 2001-11 की अवधि में स्वकषिप्त जोतों की संख्या में दशाब्दी वृद्धि 22.5 प्रतिशत थी। छोटे किसानों की संख्या की तदनुसार वृद्धि 8.9 प्रतिशत थी। इस वृद्धि के कारण इन दो खंडों का संयुक्त अंश 2001-11 की अवधि के दस वर्षों के दौरान 82 प्रतिशत से बढ़कर 85 हो गया।

अब सीमांत और छोटे किसान कुल स्वकषिप्त क्षेत्रफल के 44 प्रतिशत और स्वकषिप्त जोतों की संख्या के 85 प्रतिशत हैं। देश के किसानों के 85 प्रतिशत को आजीविका निर्वाह आवश्यकताएं भारत के लिए मुख्य विकास और नीति चुनौतियों में से एक है। भारतीय कृषि अपनी छोटी जोतों के स्वरूप के कारण यांत्रिक खेती प्रारंभ करने में असमर्थ रही है और जब तक विशाल स्तर में विस्तार कार्यक्रम नहीं चलता है। नई प्रौद्योगिकी का अंगीकरण कठिन है। कृषि वृद्धि को धारणीय बनाए रखने और खाद्य सुरक्षा का उद्देश्य प्राप्त करने का एकमात्र रास्ता आदतों जैसे सिंचाई, बिजली, उर्वरक, कीटनाशक, तकनीकी जानकारी, िड्डूक बीज, आधार मूल संरचना विकास और बाजार समर्थन आदि बड़ी हुई सरकारी सहायता है।

बड़े हुए आदान के वित्तीय भार का बड़ा भाग सरकारी सहायता के द्वारा पूरा करना होगा। इसलिए छोटे किसानों की आवश्यकताएं डब्ल्यूओ वार्ताओं में यथाविधि हल की जानी चाहिए, क्योंकि यह किसान विकसित देशों के विशाल आकार की यांत्रिक खेती से प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते हैं। बाजार सुलभता और संयुक्त राष्ट्र जापान तथा अन्य विकसित देशों में दी गई निर्यात सहायता और घरेलू सहायता की कटौती के अभाव में अन्य देशों द्वारा वचनबद्धता की पूर्ति के बिना व्यापार उदारीकरण नीतियों का अनुसरण किया जाता है तो भारत जैसे देशों को गंभीर प्रतिकूल प्रभाव भुगतने होंगे।



ग्वालियर कृषि विश्वविद्यालय में कृषि शिक्षा मेले का आयोजन

टेंगडीजी की प्रतिमा से मिलेगी समाज सेवा की प्रेरणा

कृषि में प्राप्त ज्ञान का सर्वश्रेष्ठ उपयोग कर युवा रोजगार प्रदाता बनें:राज्यपाल

ग्वालियर। जागत गांव हमार

राज्यपाल विजयराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय में कृषि शिक्षा मेला में मुख्य अतिथि के रूप में बोलते हुए प्रदेश के राज्यपाल तथा विश्वविद्यालय के कुलाधिपति मंगुभाई पटेल ने कहा कि कृषि क्षेत्र में प्राप्त ज्ञान का सर्वश्रेष्ठ उपयोग करते हुए युवाओं को रोजगार देने वाला नहीं, बल्कि रोजगार देने वाला बनना होगा। आज विश्व में भारतीय ज्ञान की महत्ता बढ़ रही है। हमारे देश के ज्ञान ने पद पर कर विश्व में देश का मान बढ़ाया है। इसी प्रकार मानव स्वास्थ्य के हित में हमारे परंपरागत अनाज मिलेट्स को दुनिया में स्वीकार्यता हो रही है। ऐसे में

हमारे बच्चे कृषि में अच्छी शिक्षा प्राप्त करें तथा देश की प्रगति में अपना योगदान दें। राज्यपाल ने अपने उद्बोधन में कहा कि कृषि मेले का आयोजन विद्यार्थियों को शिक्षित व सांस्कारित करने की पहल है। वैश्वीकरण के क्रम में कृषि में बदलाव आ रहे हैं। आज हमें खाद्यान्न सुरक्षा तथा टिकाऊ खेती के क्षेत्र में करते हुए ग्रामीण युवा तथा महिलाओं के जीवन में परिवर्तन लाने हैं। जलवायु परिवर्तन जल संकट, रासायनिक कीटनाशकों उर्वरक के अत्यधिक उपयोग से उत्पन्न संकट का सामना करने के लिए प्राकृतिक खेती की ओर बहुत अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है।

आधुनिक खेती के लालच से किसानों को हो रहा भारी नुकसान

विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफसर अरविंद कुमार शुक्ला ने संबोधित करते हुए कहा कि कृषि विज्ञान एक व्यापक व पुरातन विज्ञान है। विश्व के प्राचीनतम ग्रंथ ऋग्वेद में कृषि का गौरवपूर्ण इतिहास मिलता है। कृषि ही मानव जीवन का आधार है। उन्होंने कहा कि समय के साथ कृषि का परिदृश्य बदल रहा है। परंपरागत खेती कई सालों से प्रचलित है, परंतु आधुनिक खेती में हमारी जरूरत से ज्यादा हमारा लालच बढ़ गया है इसलिए इससे हमें काफी नुकसान भी हुए हैं। उन्होंने कृषि शिक्षा के महत्व को रेखांकित करते

हुए बताया कि देश में 75 सरकारी तथा 30 निजी कृषि विश्वविद्यालय 600 कृषि कॉलेज आज कृषि शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। इस क्षेत्र में कृषि, उद्यानिकी, मछलीपालन, पशुपालन, कृषि प्रौद्योगिकी आदि में अपार संभावनाएं हैं। आज स्मार्ट एग्रीकल्चर तकनीक आधारित कृषि की जा रही है 2200 स्टार्टअप देश में एपी इंटरस्ट्री आधारित चल रहे हैं। कृषि के अनुसंधान, विस्तार कार्य करने में नवीन तकनीकों का समावेशन तभी समय होगा जब हम कृषि में उच्च शिक्षा देकर कार्यदक्ष मानव संसाधन तैयार करें।

कृषि शिक्षा में वर्तमान में छात्रों का प्रतिशत 23 से बढ़कर 49 फीसदी हुआ

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली के उपमहानिदेशक (कृषि शिक्षा) डॉ. आरसी अग्रवाल ने कहा कि वर्तमान में शिक्षा के महत्व को जानना महती आवश्यकता है। देश में कृषि शिक्षा के प्रति विद्यार्थियों में रुची बढ़ रही है। इस वर्ष कृषि शिक्षा में प्रवेश के लिए 6 लाख 80 हजार आवेदन प्राप्त हुए हैं। कृषि शिक्षा में वर्तमान में छात्रों का प्रतिशत 23 से बढ़कर 49 प्रतिशत हो गया है। हमें आधुनिक कृषि को सस्टेनेबल लेवल से कर्मिश्यल स्तर पर ले जाने की आवश्यकता है। इस अवसर पर विश्वविद्यालय के विभिन्न कृषि विज्ञान केन्द्र द्वारा लगायी गई आकर्षक प्रदर्शनी का राज्यपाल द्वारा उद्घाटन किया गया। कार्यक्रम के द्वितीय सत्र में विभिन्न विद्यालयों से आये प्राथमिक कृषि शिक्षा के विभिन्न आयामी इसमें उपलब्ध अवसरों के विषयों में विद्वानद्वारा जानकारी दी गई।

शुष्क अंतराल बढ़ने से सोयाबीन और धान को नुकसान, 8 सितंबर तक सूखे की स्थिति गंभीर होने के हालात

चिंता में अन्नदाता...बारिश की आस में बरबादी की ओर चली फसल

भोपाल। जागत गांव हमार

मौसम की बेरुखी ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। बारिश का अंतराल बढ़ने से सोयाबीन और धान की 25 प्रतिशत तक फसल खराब होना इसकी बड़ी वजह में शामिल है। कृषि उत्पादन में इसका प्रतिकूल इसलिए भी पड़ सकता है, क्योंकि हाल-फिलहाल के हालात सूखे जैसी गंभीर स्थिति में लाकर खड़ा करने वाले हैं। क्योंकि कम बारिश के बीच प्रदेश में अब बारिश के असर सप्ताह भर बाद बन रहे हैं। यह तब और महत्वपूर्ण हो जाता है जबकि प्रदेश औसत बारिश के आंकड़े से करीब 19 इंच दूर खड़ा है। हालांकि 8 सितंबर के बाद एक बार फिर बारिश के आसार हैं, लेकिन नुकसान को भरपाई को लेकर मौसम विभाग भी कुछ कहने की स्थिति में नहीं है। भिंड-मुरैना, सतना, उमरिया, धार, आगर मालवा और नीमच जैसे क्षेत्रों में मिडल ड्राय स्पेल की कगार में खड़े हैं। कृषि वैज्ञानिकों की माने तो यह स्थिति प्रदेश को सूखे की ओर ले जा सकती है। कम पानी की मार फसल बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। क्योंकि फसल को जहां कीट पतंगे नुकसान पहुंचा रहे होंगे। वहीं दूसरी ओर पानी नहीं मिलने से दाना बनने से पहले यह सूख जाएगा।

135 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में हुई खरीफ बुवाई

प्रदेश में इस बार खरीफ बुवाई का रकबा 135 लाख हेक्टेयर तय किया गया है। अब 134.05 लाख हेक्टेयर में बुवाई हो गई है। इसमें प्रमुख तिलहनी फसल सोयाबीन की बोनी 50 लाख हेक्टेयर है। जबकि धान की बुवाई 28.27 लाख हेक्टेयर में हुई है।



इसलिए कम बारिश प्रदेश में 1 जून से 31 अगस्त तक औसत 26.05 इंच बारिश हो चुकी है, जबकि अब तक 30.81 इंच बारिश होनी चाहिए थी। मौसम विभाग का कहना है कि अगस्त महीने में 7.94 इंच पानी गिरा है, जबकि 13.15 इंच बारिश होनी चाहिए थी। इस हिसाब से करीब 40 प्रतिशत तक पानी कम गिरा है। बीते दस सालों में यह पहला मौका है जबकि भोपाल में इस बार सबसे कम 4.23 इंच पानी गिरा है। 11 साल में 4 बार ऐसा हुआ, जब 10 इंच से कम बारिश हुई हो। पिछले साल बारिश ने रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। यहां 30 इंच से ज्यादा बारिश हो गई थी।

■ बनते-बिगड़ते मौसम से प्रदेश का किसान परेशान है। करीब 25 प्रतिशत सोयाबीन और इतना ही धान की फसल खराब हो गई है। पानी नहीं गिरा तो स्थित बिगड़ सकती है। बड़नगर पहुंचने पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के संज्ञान में यह विषय संघ लागू। किसानों को राहत देने पर विचार करना चाहिए।
■ कमल सिंह आंजना, प्रदेश अध्यक्ष भारतीय किसान संघ
■ प्रदेश ड्राई स्पेल से जूझ रहा है। बढ़ता अंतराल फसलों की उत्पादकता पर असर डालेगा। सोयाबीन के लिये सप्ताह में एक दिन पानी की जरूरत है। पर कई जिलों में 15 दिन तक नहीं मिल रहा है। मानसून निर्भर किसानों के लिए यह स्थिति नुकसान की ओर ले जाने वाली है।
■ डॉ. एसपी सिंह, प्रधान कृषि वैज्ञानिक एवं प्रमुख कृषि विज्ञान केंद्र भिंड
■ प्रदेश में बारिश का दौर फिलहाल 8 सितंबर के आस-पास शुरू होने की संभावना है। औसत बारिश के लिये अभी 19 एमएम पानी की आवश्यकता बनी हुई है। पश्चिम मध्य प्रदेश में 20 प्रतिशत और पूर्वी क्षेत्र में 13 प्रतिशत कम बारिश दर्ज की गई है। दैले भी सामान्य बारिश की संभावना है।
पीके साहा, सेवानिवृत्त वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक



श्योपुर में बह रही 28 नदियां, इनमें 10 बनीं नाला, कुछ पर हो रही खेती

दौनी, पारम, सरारी, कदवाल, नदियां विलुप्त होने की कगार पर

सरकार! विलुप्त होती जा रही अमृत बांटने वाली नदियों को 'अमृत 2.0' की दरकार

श्योपुर। जागत गांव हमारा

मध्यप्रदेश का श्योपुर जिला ग्वालियर चंबल संभाग का सबसे अधिक नदियों वाला जिला है। जिले में छोटी बड़ी कुल 28 नदियां बह रही हैं। जो जिले के को कृषि, वन संपदा को बढ़ाने के साथ-साथ वनवासियों, वन्यजीवों, मवेशियों का जीवन बचाने का काम कर रही हैं। अपना अमृत समान नीर (जल) बांटने वाली इन जीवन दायिनी नदियों को बचाने और इनके पुनरुद्धार के लिए अमृत 2.0 जैसी योजना की दरकार है।

ग्वालियर चंबल संभाग में श्योपुर में 28 नदियां कभी बारहों महीने बहती थीं, लेकिन पिछले दो दशक से धीरे-धीरे यह नदियां दम तोड़ती जा रही हैं जिसके चलते अब दर्जनभर नदियां तो सिर्फ नक्शों में ही रह गई हैं। जिले में पिछले सालों में लगातार औसत से ज्यादा बारिश हुई है। फिर भी 10 नदियां सूखकर नाला बनकर रह गई हैं। नदियों के प्राकृतिक बहाव क्षेत्र में खेती के लिए कच्चे और अवैध निर्माण ने रास्ता रोक दिया है। मानवीय भौतिक संसाधनों की पूर्ति के चलते वन, वन्यजीव और जलाशयों जैसे प्रकृति से उपहार में मिली धरोहरों को नुकसान पहुंचाने का काम तो मानव प्रवृत्ति बन ही गया है। नदियों के किनारे जगह जगह खेती कर अप्राकृतिक संसाधनों से लगातार किए जाने वाले दोहन के चलते बारहमासी यह नदियां सिर्फ बरसाती नाले बनकर रह गई हैं। कई जगह तो अत्यधिक दोहन से मन नहीं भरा तो नदियों में ही अतिक्रमण कर नदियों का बहाव विपरीत दिशा में मोड़कर प्राकृतिक आपदा को बुलावा भेजने का काम भी खूब किया जा रहा है। इन नदियों को बचाने के लिए मनरेगा सहित दूसरी योजनाओं के माध्यम से खूब पैसा पानी की तरह बहाया लेकिन जिस जगह पैसा बहाया गया वहां भी पानी रुकने का नाम नहीं ले रहा है। जलाशयों के पुनरुद्धार और उन्हें पुनर्जीवित करने के उद्देश्य से केंद्र द्वारा चलाई गई अमृत 2.0 योजना की भी अब अतिआवश्यकता इन नदियों को बचाने के लिए पड़ गई है।



अवैध खनन व बढ़ते प्रदूषण से जलचरों को खतरा

मालवांचल से निकली चंबल नदी कोटा होते हुए श्योपुर जिले में पाली पर प्रवेश करती है। इसी जगह चंबल नदी के साथ पार्वती नदी का संगम होता है। पाली घाट से वीरपुर तक लगभग 70 किलोमीटर लंबे दायरे में चंबल नदी का घटना जलस्तर और बढ़ता प्रदूषण सबसे बड़ी समस्या है। चंबल नदी में बढ़ते जल प्रदूषण के कारण जलचरों की कई प्रजातियां का अस्तित्व खतरे में है। रेत का अवैध उत्खनन घड़ियालों के प्रजनन में बाधक है। वहीं पार्वती नदी का उद्गम राजस्थान के फूसोद कस्बे से माना जाता है। पार्वती नदी बड़ीधिया बिंदी के पास श्योपुर जिले में प्रवेश करती है। नदी के दोनों किनारे जमीन अतिक्रमण है।

इन नदियों के अस्तित्व पर मंडरा रहा संकट

जिले में अहेली, कदवाल, अमराल, सरारी, पारम, दौनी, भादड़ी, ककरेंडी, दुआर, अहेली सहित कई बरसाती नदियां अस्तित्व के संकट से जूझ रही हैं। यह सभी नदियां सिर्फ बारिश के समय बहती हैं, लेकिन इनमें जगह जगह पानी पूरे साल भरा रहता है जिससे वन्यजीव और वनवासी अपने मवेशियों को प्यास बुझाते रहते हैं। ऐसे प्राकृतिक पोखरों पर भी कच्चे होने के चलते यह नदियां मानसून की विदाई के बाद सखी में ही सूखकर नाला बनने लगी हैं। प्रशासन इन नदियों पर स्टोप डेम बनाकर इन्हें विलुप्त होने से बचा सकता है।

शहर से गुजरी नदियां अधिक मैली

शहर सहित जिले के सवा सौ गांव की जीवनरेखा सीप नदी का उद्गम कराहल के पनवाड़ा से बताया जाता है। गोरस, पनार, मऊ होती हुई श्योपुर, जाटखेड़ा, सोईकला, गुरनवादा, शंकरपुर, मेवाड़ा, बहरावादा, मानपुर से रामेश्वर में चंबल व बनस नदियों में मिलकर त्रिवेणी का पवित्र संगम बनाती है। शहर के सभी 18 गंदे नाले इसी नदी में मिलते हैं। हर साल गर्मी आते ही सूख जाती है। सीप नदी में सिर्फ गंदे नाले बहाने के कारण इसका पानी सड़ांध मारने लगा है। यही हाल वनांचल से गुजरी कुनो नदी और कुवारी नदी का है। यही हाल विजयपुर नगर के बीच से गुजरी छात्री नदी का है इस नदी को भी कई जगह पर कचरा डालने का स्थान बना रखा है।

कच्चे से सिकुड़ी स्वच्छंद बहती नदियां

कल-कल बहती नदियों के लिए पहचाने जाने वाले श्योपुर जिले में अब यह गुजर जमाने की बात हो चली है। लोगों ने तुच्छ स्वार्थ की खातिर नदियों को नाला बना डाला है। श्योपुर-सवाई माधोपुर इंटर स्टेट हाईवे पर जिला मुख्यालय से 10 किलोमीटर दूर ग्राम सोईकला से होकर गुजरी ककरेंडी नदी एक बरसाती नदी है। इसके किनारे कच्चे करके कई साल से खेती हो रही है। सोईकला के पास ककरेंडी नदी के रास्ते में आलीशान ढाबा बना गया है। यह ढाबा पिछले एक साल से चल रहा है। स्थानीय लोगों ने बताया कि नदी किनारे खाली जमीन को खेल मैदान के लिए आवंटित करने की मांग की थी। लेकिन खेल मैदान व इसके आसपास की नदी की तलहटी तक जगह घेरकर ढाबा बना दिया गया। ढाबा मालिक के रसूख के चलते कोई कार्रवाई नहीं हुई है। वर्तमान में गड्डे में सिमटी ककरेंडी नदी सिर्फ बारिश के मौसम में ही बहती है। साल के 8 महीने अधिकांश स्थानों पर सूखकर मैदान नजर आती है।

2021 ने भुगता प्रकृति से टकराव का नतीजा

प्रकृति के विपरीत और उससे टकराव का नतीजा क्या होता है इसकी बानगी 2021 में जिलावासी देख चुके हैं। 3 अगस्त 2021 को आई बाढ़ की विभीषिका में शहर सहित एक सैंकड़ा गांव डूब गए थे। हालांकि पानी का जलस्तर अधिक बढ़ जाने से बाढ़ आई थी, लेकिन अधिकतर नुकसान वहां हुआ जहां लोगों ने नदी के रास्ते में कब्जा कर उसे दूसरी ओर मोड़ दिया था। ऐसे स्थानों पर नदी ने बस्तियों में घुसकर अधिक प्रलय मचाई लोगों का कहना है कि बाढ़ के समय नदियों को प्राकृतिक रूप से बहने का रास्ता मिलता तो तबाही का मंजर बहुत हद तक कम होता।

परिषद ने मेजा सीप के संरक्षण का प्लान

नगर पालिका परिषद ने सीप को कोटा के चंबल गार्डन और चंबल नदी की तर्ज पर विकसित करने के लिए अमृत 2.0 योजना के तहत प्रस्ताव शासन को भेज दिया है। परिषद ने जो प्लानिंग की है उसके तहत तिलमेश्वर महादेव घाट गुलाबबाड़ी से बंजारा डेम तक घाटों के बीच कोरिडोर बनाने नदियों के दोनों ओर पार्क और रेस्टॉरेंट विकसित करना शामिल है। अगर नगरपालिका का यह प्लान सफल होता है तो दम तोड़ती सीप को भी नया जीवन मिल जाएगा। ज्ञातव्य हो की सीप में नालों को जाने से रोकने के लिए नगरपालिका में सीवर ट्रीटमेंट प्लांट को भी स्वीकृत कराने के लिए अमृत 2.0 योजना में प्रस्ताव शासन को भेजा है।

फसल सुरक्षा के लिए समसामायिक सलाह

सोयाबीन में आशिक पीला मौजेक और उड़द-मूंग में विषाणु फफूंद का अटैक

नरसिंहपुर। जगत गांव हमार

कृषि विज्ञान केन्द्र एवं कृषि विकास एवं किसान कल्याण विभाग नरसिंहपुर के वैज्ञानिकों एवं अधिकारियों के लगातार खरीफ में लगाए गए प्रमुख फसलों जैसे सोयाबीन, उड़द, मूंग, धान, मक्का के साथ ही गन्ने में रोग/कीट के लिए सर्वेक्षण किया गया। उपरोक्त सर्वे के आधार पर जिले के कृषकों को खरीफ फसलों के लिए फसलवार समसामायिकी सलाह प्रदाय की जा रही है। जिसे किसान भाई समय पर अपनाकर फसल सुरक्षा कर सकते हैं। सोयाबीन फसल में आशिक रूप से पीला मौजेक का प्रकोप देखा गया। साथ ही कहीं-कहीं चारकोल रॉट का भी प्रभाव पाया गया। उड़द व मूंग में पीला विषाणु रोग के साथ ही पत्तियों पर सरकोस्पोरा फफूंद के आक्रमण पाया गया है, जिससे पत्तियों पर भूरे धब्बे दिखाई दे रहे हैं। धान की फसल में सीथ ब्लाइट के साथ ही पत्तियों पर धान के झुलसा रोग का आपतन कुछ धान की प्रजातियों में पाया गया है। धान का फूटका कीट (हरा व सफेद फूटका) का प्रकोप खेत में जगह-जगह गोलाई में देखा जा रहा है। सोयाबीन के साथ ही उड़द मूंग के विषाणु रोग का वाहक सफेद मक्खी है के नियंत्रण के लिए थायोमेथाक्जाम या इमिडाक्लोप्रिड 17.8 प्रतिशत, 500-600 मिली प्रति हेक्टेयर 500-600 लीटर पानी के साथ छिड़काव करें। जहां चारकोल जड़ सड़न का प्रकोप दिखे वहां टेब्रकोनोजोल प्लस सल्फर 900-1000 मिली/हेक्टे. 500 लीटर पानी के साथ छिड़काव करें। उड़द-मूंग में पत्ती धब्बा रोग नियंत्रण के लिए कार्बेन्डाजिम प्लस मैकोजेब 1000 ग्राम प्रति हेक्टे. 500 लीटर पानी के साथ छिड़काव करें।



धान में जहां पानी लगा होगा, वहां सीथ ब्लाइट का प्रकोप होना स्वाभाविक

धान में फूटका नियंत्रण के लिए फीप्रोनील 40 : इमिडाक्लोप्रिड 40 : की दवा 150-200 ग्राम प्रति हेक्टेयर 500 लीटर पानी के साथ छिड़काव कराएँ साथ ही धान में झुलसा नियंत्रण के लिए कासुगामाईसिन 1000 ग्राम या ट्राइसाक्लोजोल 200 ग्राम/हे. का छिड़काव लक्षण की शुरूआत में करने पर तत्काल नियंत्रण संभव है। यदि रोग का प्रकोप ज्यादा हो तो पन्द्रह दिन पश्चात फफूंदनाशक ही बदल कर छिड़काव करें। मक्का व ज्वार में फाल आमीवम के साथ ही अन्य कीटों को आपतन पाया गया। इनके नियंत्रण हेतु इमेक्टिन बेन्जोएट 200 ग्राम प्रति हेक्टे या ज्यादा प्रकोप होने पर क्लोरेन्टानिलीप्रान 100 ग्राम/हे. 500 लीटर पानी के साथ छिड़काव करें। धान में जहां पानी लगा होगा। वहां सीथ ब्लाइट का प्रकोप होना स्वाभाविक है। इसके नियंत्रण के लिए हेवसाकोनो जेन 1000 मिली/हे. 500-600 लीटर पानी के साथ छिड़काव करें। गन्ने में बोक्का बोइंग रोग का प्रकोप है। पावर स्पेयर से कार्परआवसीवलोराइड या मैकोजेब पानी के साथ छिड़काव करें।

फोटो मेजकर दवा की जानकारी प्राप्त कर ही प्रयोग करें

जो किसान भाई जैविक खेती कर रहे हैं वे सफेद मक्खी नियंत्रण के लिए एटीसिलियम लिफेनी 1000 मिली व इली नियंत्रण के लिए बेरिखा बेसियाना 1000 ग्राम/हे. के साथ ही यलो स्टीकी कार्ड 20-25 हेक्टे. खेत में चूसक कीट नियंत्रण के लिए व फेरोमोन ट्रेप 10 प्रतिहेक्टे. वयस्क पत्ती काटने वाले कीट के भेल को नियंत्रण के लिए प्रयोग करें। प्रकृति प्रदत्त उत्पादों/संशोधनों जैसे नीम, धतूरा, ओक, महुआ, अदरक आदि के अर्क को नियंत्रण कर पूर्व प्रकाशित फरमूलानुसार प्रयोग करें। रोग एवं कीट से प्रभावित फसलों के नमूने कृषि विज्ञान केन्द्र के वैज्ञानिकों को दिखा करके या केन्द्र के द्वारा बनाए गए ब्लाटसेप ग्रुप में रोग एवं कीट से ग्रहित फसलों की साफ सुथरी फोटो भेजकर दवा की जानकारी प्राप्त कर ही प्रयोग करें।



वैज्ञानिकों ने खेत में जाकर देखी फसल

उन्नत बीज उत्पादन में रॉगिंग करने के फायदे

टीकमगढ़। जगत गांव हमार

कृषि विज्ञान केन्द्र टीकमगढ़ के प्रधान वैज्ञानिक एवं प्रमुख डॉ. बीएस किरार साथ ही केन्द्र के वैज्ञानिक डॉ. आरके प्रजापति, डॉ. यूएस धाकड़, डॉ. आईडी सिंह, जयपाल छिगारहा द्वारा किसानों के खेतों का भ्रमण किया गया। भ्रमण के दौरान वैज्ञानिक डॉ. सुनील कुमार जाटव द्वारा किसानों को बताया गया कि खरीफ की दलहनी, तिलहनी एवं अनाज वाली फसलों में बीज उत्पादन करने के लिए रॉगिंग (विजातीय पौधों) को अपने खेत से निकल दें। रॉगिंग में अवांछनीय पौधों की पहचान पौधों की ऊंचाई, पत्ती का आकार, फूलों का रंग, फली का आकार, फली का प्रकार एवं आकार आदि गुणों के आधार पर करके मुख्य फसल से निकाल देना चाहिए। किसी भी प्रकार के रोग प्रस्त पौधों को निकाल दें अन्यथा बीज की गुणवत्ता

प्रभावित हो सकती है। उत्पादन कर रहे हैं तो खड़ी फसल वाले खेत में से दूसरी प्रजातियों के पौधों को निकल देना चाहिए। बीज उत्पादन में शुद्ध बीज उत्पादन के लिए रॉगिंग की क्रिया पौधों की अलग-अलग अवस्थाओं में की जाती है। बोवनी के 30 दिन बाद एवं फली बनने के बाद विजातीय पौधों या अलग किरसों के पौधों को निरीक्षण कर निकल देना चाहिए, क्योंकि विजातीय पौधों के मिलने से बीज मिश्रण हो जाएगा जिससे शुद्ध बीज प्रभावित होगा। साथ ही फसलों में पृथक्करण की दूरी को अवश्य बनाए रखें, जो किसान भाई अपने घर के लिए बीज बनाना चाहते हैं वह खेत में खड़ी फसल से ऑफ टाईप (अवांछनीय) पौधों को फसल वाले खेत से निकल दें जिससे उच्च गुणवत्ता का बीज प्राप्त हो सके।

-गोवंश के ब्लाड सैंपल की अब नहीं कराई जाएगी जांच

शहर में फैला लंपी वायरस लक्षण के आधार पर माना जाएगा पॉजिटिव

भोपाल। शहर में फैल चुके लंपी वायरस के अब जो भी केस सामने आएंगे उनकी सैंपलिंग नहीं कराई जाएगी। बल्कि गौवंश में आने वाले लक्षणों के आधार पर ही उसे लंपी संक्रमित मानकर तय प्रोटोकॉल के तहत ही इलाज किया जाएगा। यही नहीं, इन गौवंश को लंपी संक्रमित की सूची में शामिल भी किया जाएगा। पशु चिकित्सा विभाग के अधिकारियों का कहना है कि हर गौवंश का ब्लाड सैंपल लेकर जांच कराना जरूरी नहीं है। रिपोर्ट पॉजिटिव आने पर जो इलाज दिया जाता है, वह हम गौवंश में नजर आने वाले लक्षण के आधार पर देते हैं। बीते साल भी यही तरीका अपनाया गया था। शहर में अब तक 32 गौवंश लंपी संक्रमित पाए गए हैं। इनमें 19 आवारा तो बाकी के 13 पशु मालिकों के हैं। 5-7 दिन में रिकवरी हो रही है। रिकवरी होने पर आवारा पशुओं को पशु आश्रय स्थल आसरा से निगम की गोशाला भेजा जाएगा।

राजस्थान में मुआवजे का प्रावधान: बीते साल लंपी के संक्रमण का कहर सबसे ज्यादा राजस्थान में ही नजर आया था। वहां भारी लायट में गोवंश की मौत हुई थी। ऐसे में राजस्थान सरकार ने एक गाय की मौत पर किसान को 40 हजार का मुआवजा दिया था। हालांकि, मग्न में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है।

एक बार लंपी संक्रमण की पुष्टि संपत्त की जांच में हो गई है। अब सभी गौवंश की जांच करना जरूरी नहीं है। लक्षण के आधार पर गोवंश को पॉजिटिव मानकर इलाज होगा।

डॉ. अजय रामटेके, उपसंचालक, पशु चिकित्सा सेवाएं

जागत गांव हमार खेती की विज्ञान सेवा, लक्ष्य गठ

गांव हमार के सुधि पाठकों...

- » जागत गांव हमार कृषि, पंचायत और ग्रामीण विकास आधारित समाचार पत्र है, जिसके लिए आपका स्नेह और प्यार हमें शुरू से मिलता रहा है। हम आशा और विश्वास करते हैं कि आगे भी मिलता रहेगा।
- » समाचार पत्र के लिए विशेषज्ञों की राय, प्रकाशन योग्य सामग्री के साथ-साथ आपके समक्ष इसे पहुंचाने तक हमारी जिम्मेदारी बड़ी चुनौतीपूर्ण है। आपके सहयोग से ही हम इस चुनौती का सामना कर पाएंगे।
- » ऐसे में हमारी आपसे अपेक्षा और आग्रह है कि जागत गांव हमार के वार्षिक सदस्य बनें और इसके लिए नीचे लिखे गए नंबर पर संपर्क करें।

संपर्क करें- अजय द्विवेदी-9229497393, 94250485889

“आपका सहयोग हमारी मजबूती का आधार बनेगा”



मोपाल की प्रदर्शनी में खरगोन के पौधे होंगे आकर्षण का केंद्र

पर्यावरण संवर्धन में खरगोन की 7 नर्सरियों का योगदान

महिला स्व सहायता समूहों को नर्सरियों में दिया रोजगार मनरेगा से तैयार कराये विभिन्न प्रजातियों के 12 लाख पौधे

खरगोन। जागत गांव हमार

भीषण गर्मी, गिरता भूमि का जलस्तर और जमीन पर चलती लपटों से खरगोन को राहत देने के प्रयास शुरू हो चुके हैं। यहां महिला स्व सहायता समूहों को मनरेगा से रोजगार उपलब्ध करते हुए उनसे पौधे तैयार करवाए जा रहे हैं। कलेक्टर शिवराज सिंह वर्मा के निर्देशन में अब तक इस नवाचार से विभिन्न प्रजातियों के 12 लाख से अधिक पौधे तैयार

किए जा चुके हैं। बारिश से पूर्व मनरेगा के तहत योजना बनाई गई। महिला स्व सहायता समूहों से एक-एक नर्सरियां तैयार कराई गईं। महिला समूहों ने बानिकी, फल और फूलों वाले पौधे तैयार किए। अब ये पौधे वृक्षारोपण अभियान में उपयोग में लाए जा रहे हैं। मेरी माटी-मेरा देश अभियान के दौरान प्रत्येक पंचायतों में 75-75 पौधे इन्हीं नर्सरियों के उपयोग किए गए। इस नवाचार में एक ओर स्व सहायता समूहों को 221 रुपए की प्रतिदिन मजदूरी के साथ पौधों की बिक्री में 50 प्रतिशत की राशि उनकी होगी।



हर समूह के 50.34 लाख के प्रस्ताव बनाए

मनरेगा के तहत जिला पंचायत व उद्यानिकी विभाग के माध्यम से महिला समूहों को जिले की 7 नर्सरियों में नर्सरी तैयार कराई गई। इसके लिए प्रत्येक समूहों को 50.34 लाख की राशि के प्रस्ताव तैयार कराए गए। जिसमें नर्सरी स्तर पर संसाधनों पर स्वीकृत राशि खर्च की गई। महिला समूहों की सक्रियता से नर्सरियां पूरी क्षमता से काम कर रही हैं। यहां 21 प्रजाति के फल, 13 प्रजाति के बीज से तैयार पौधे, पांच किस्म के बानिकी और सजावटी पौधे तैयार किए जा रहे हैं।

पौधों की सरकारी मांग ज्यादा

कसरावद जनपद में रसीदपुरा में मां अम्बे स्वामी बलराम नर्सरी का संचालन कर रहे हैं। समूह के सचिव सुनील मंडलोई ने बताया कि सरकारी अभियानों के पौधरोपण और ग्राम पंचायतों में पौधे सप्लाय किए गए हैं। झिरन्या के धनवा गांव की महिला स्व सहायता समूह के सचिव दीवानसिंह ने बताया कि पंचायतों में पौधरोपण अभियान चलाएंगे तो समूह सप्लाय करता है।

महिला समूह के तैयार पौधे

सेगांव में 14552, खरगोन 106326, भीकनगांव 46446, झिरन्या 167003, गोगावां 189583, भगवानपुरा 131273, बड़वाह 110899, कसरावद 148618, महेश्वर 141020 की नर्सरी में कुल 1152695 पौधे तैयार हैं। इनके अलावा नर्सरी में 50011 शोभायमान पौधे भी उपलब्ध हैं।



Dhani Seeds

Bringing Growth In Agri

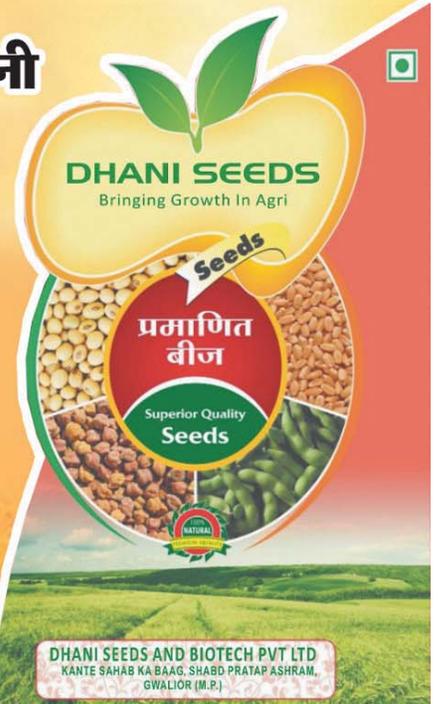
धानी सीड्स एंड बायोटेक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी

द्वारा किसानों के लिए अच्छी क्वालिटी के बीज तैयार किए जाते हैं। रबी सीजन 2023-24 में गेहूं की किस्म

किस्म

विशेषता

GW-322	उत्पादन 58-60 कि. प्रति हेक्टेयर	सिंचाई 3 से 4। दाना मध्यम आकर
HI-1544(पूर्णा).	उत्पादन 57-59 कि प्रति है.	दाना सरबती जैसा रोटी के लिए उत्तम गेहूँ
HI-8759 (पूसा तेजस)	उत्पादन 60-62 कि प्रति है.	4-5 सिंचाई, सूजी दलिया के लिए सबसे ज्यादा उपयोग।
RAJ-4037	उत्पादन 57-58 कि प्रति है.	2 से 3 सिंचाई, बोने के लिए अगेती और पखेती किस्म, दाने का आकर बड़ा और चमकदार, रोटी के लिए उत्तम गेहूँ
RAJ-4238	उत्पादन 59-60 कि प्रति है.	2 से 3 सिंचाई करनाल बंट के प्रति रोगप्रतिरोधक क्षमता, दाना बड़ा और चमकदार।
HI-8737 (पूसा अनमोल).	उत्पादन। 60-62 कि प्रति है.	4-5 सिंचाई कौटो सेगों के प्रति रोग प्रतिरोधक क्षमता।
Unnat-Pbw-343	उत्पादन 59-61 कि प्रति हेक्टेयर दाना बड़ा चमकीला।	बोने का समय 7 से 25 नवंबर



बीजों की जानकारी और कीमत जानने के लिए संपर्क करें 9691454023-whatsapp

Address- Kante Sahab Ka baag, Shabd Pratap Ashram, Gwalior-संपर्क करें- 8602919196, 9926229407

DHANI SEEDS AND BIOTECH PVT LTD
KANTE SAHAB KA BAAG, SHABD PRATAP ASHRAM,
GWALIOR (M.P.)